अंतर्देशीय जलमार्गों पर भारत का रिकॉर्ड माल परिवहन

***

वित्त वर्ष 2024-25 में 145.5 मिलियन टन का लक्ष्य हासिल

***

24 अप्रैल, 2025
नई दिल्ली

महत्वपूर्ण उपलब्धियां

भारत ने वित्त वर्ष 2024-25 में अंतर्देशीय जलमार्गों पर रिकॉर्ड 145.5 मिलियन टन कार्गो आवाजाही के लक्ष्य को हासिल किया। यह वित्त वर्ष 2013-14 के 18.1 मिलियन मीट्रिक टन (एमएमटी) से अधिक है और इसमें 20.86 प्रतिशत की सीएजीआर दर्ज की गई है।

राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या 5 से बढ़कर 111 हो गई है, 2014-15 में परिचालन दूरी 2,716 किलोमीटर थी, जो 2023-24 में बढ़कर 4,894 किलोमीटर हो गई।

मल्टी-मॉडल टर्मिनल (एमएमटी), इंटर-मॉडल टर्मिनल (आईएमटी), सामुदायिक जेटी, फ्लोटिंग टर्मिनल और हाइब्रिड इलेक्ट्रिक और हाइड्रोजन वेसल्स जैसी हरित तकनीक सहित बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे का विकास हुआ है।

95.42 करोड़ रुपये के बजट के साथ जलवाहक योजना का शुभारंभ, प्रमुख मार्गों (एनडब्ल्यू-1, एनडब्ल्यू-2, एनडब्ल्यू-16) पर कार्गो मालिकों और अनुसूचित सेवाओं के लिए 35 प्रतिशत परिचालन लागत प्रोत्साहन की पेशकश।

भारत का लक्ष्य समुद्री अमृत काल दृष्टिकोण के तहत भारत के अंतर्देशीय जल परिवहन मॉडल शेयर को 2 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत करना और 2030 तक यातायात को 200+ एमएमटी और 2047 तक 500+ एमएमटी तक बढ़ाना है।

रिकॉर्ड कार्गो परिवहन अंतर्देशीय जल परिवहन में एक बड़ी उपलब्धि है

भारत के अंतर्देशीय जल परिवहन (आईडब्ल्यूटी) क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि के बारे में बताते हुए भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में 145.5 मिलियन टन की रिकॉर्ड-तोड़ कार्गो आवाजाही की सूचना दी। यह उपलब्धि देश के अंतर्देशीय जलमार्ग बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के उद्देश्य से निरंतर निवेश और नीतिगत पहलों की प्रभावशीलता को रेखांकित करता है। इसी अवधि के दौरान परिचालन राष्ट्रीय जलमार्गों की संख्या भी 24 से बढ़कर 29 हो गई है, जो मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी और टिकाऊ परिवहन सुविधाओं की दिशा में एक रणनीतिक कदम है।

पिछले दस वर्षों में माल यातायात में तेजी से वृद्धि

वित्त वर्ष 2014 और वित्त वर्ष 2025 के बीच राष्ट्रीय जलमार्गों पर कार्गो यातायात 18.10 (मिलियन मीट्रिक टन) एमएमटी से बढ़कर 145.5 एमएमटी (मिलियन मीट्रिक टन) हो गया है और इसमें 20.86 प्रतिशत की सीएजीआर दर्ज की गई है।

वित्त वर्ष 2025 में, यातायात की आवाजाही में वित्त वर्ष 2024 की तुलना में साल-दर-साल 9.34 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। कोयला, लौह अयस्क, लौह अयस्क चूर्ण, रेत और फ्लाई ऐश जैसी पांच वस्तुओं ने वर्ष के दौरान राष्ट्रीय जलमार्गों (एनडब्ल्यू) पर कुल माल ढुलाई में 68 प्रतिशत से अधिक का योगदान दिया। 2023-24 में यात्रियों की आवाजाही भी 1.61 करोड़ तक पहुंच गई है।

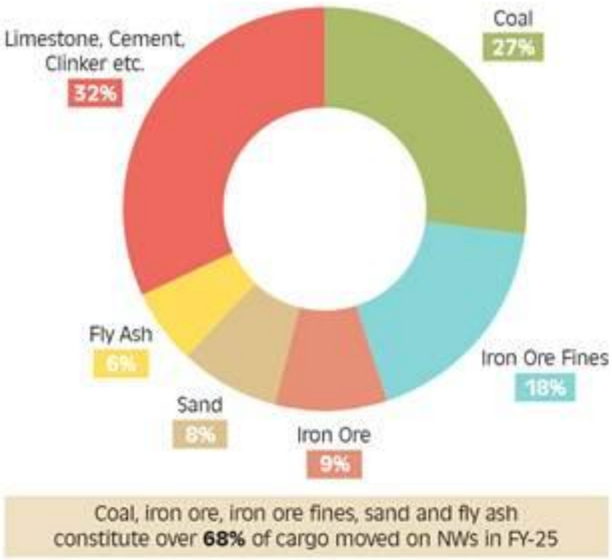

राष्ट्रीय जलमार्गों का विस्तार

पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के तहत भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) ने राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम, 2016 के तहत राष्ट्रीय जलमार्गों (एनडब्ल्यू) की संख्या 5 से बढ़ाकर 111 कर दी है। 2014 से सरकार ने जलमार्ग बुनियादी ढांचे के विकास के लिए लगभग 6,434 करोड़ रुपये का निवेश किया है।

राष्ट्रीय जलमार्गों की 2014-15 में परिचालन दूरी 2,716 किलोमीटर थी, जो 2023-24 में बढ़कर 4,894 किलोमीटर हो गई। प्रमुख कार्यों में फेयरवे रखरखाव, सामुदायिक जेटी, फ्लोटिंग टर्मिनल, मल्टी-मॉडल टर्मिनल (एमएमटी), इंटर-मॉडल टर्मिनल (आईएमटी) और नेविगेशनल लॉक शामिल हैं।

भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने व्यवसाय करने में आसानी को बढ़ावा देने के लिए कम उपलब्ध गहराई सूचना प्रणाली (एलएडीआईएस), नदी सूचना प्रणाली (आरआईएस), कार-डी, नेविगेशनल सूचना के लिए पोर्टल (पीएएनआई) और प्रबंधन सूचना और रिपोर्टिंग समाधान (एमआईआरएस) जैसे डिजिटल उपकरण लॉन्च किए। प्रदूषण को कम करने और नदी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कैटामारन और हाइड्रोजन से चलने वाली बड़ी नाव सुविधा जैसी हरित पहल शुरू की जा रही हैं।

लक्ष्य और सतत विकास

भारत सरकार ने अंतर्देशीय जलमार्गों के माध्यम से माल की आवाजाही के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए हैं। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का लक्ष्य समुद्री भारत विजन 2030 के अनुरूप आईडब्ल्यूटी के माध्यम से माल की आवाजाही के मॉडल हिस्से को 2 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत करना और यातायात की मात्रा को 200 मिलियन मीट्रिक टन से अधिक करना और समुद्री अमृत काल विजन 2047 के अनुसार 2047 तक 500 मिलियन मीट्रिक टन से अधिक करना है।

अंतर्देशीय जलमार्गों को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत उपाय

1. जलवाहक – कार्गो प्रमोशन योजना

भारत में अंतर्देशीय जल परिवहन (आईडब्ल्यूटी) क्षेत्र अभी भी विकसित हो रहा है और माल की ढुलाई सड़क और रेल की जगह जलमार्गों से करने के लिए समर्थन की आवश्यकता है। आमतौर पर जलमार्ग परिवहन सस्ता है, लेकिन मल्टीमॉडल हैंडलिंग के कारण समग्र रसद लागत अधिक हो सकती है। इसका समाधान करने और आईडब्ल्यूटी को बढ़ावा देने के लिए 15 दिसंबर, 2024 को 95.42 करोड़ रुपये के बजट के साथ "जलवाहक" योजना शुरू की गई। इसके दो प्रमुख घटक हैं:

1. वित्तीय प्रोत्साहन: मालवाहक मालिकों को सड़क/रेल की बजाय आईडब्ल्यूटी से माल ढुलाई करने के लिए वास्तविक परिचालन लागत पर 35 प्रतिशत प्रतिपूर्ति मिलती है, जिससे जलमार्गों के उपयोग को बढ़ावा मिलता है।
2. अनुसूचित सेवाएं: विश्वसनीयता और पूर्वानुमानशीलता को बढ़ाने के लिए नियमित कार्गो सेवाएं शुरू की गई हैं।

प्रमुख मार्ग इस प्रकार हैं:

- कोलकाता-पटना-वाराणसी (राष्ट्रीय जलमार्ग-1)
- कोलकाता-पांडु (भारत-बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग से राष्ट्रीय जलमार्ग-2)
- कोलकाता-बदरपुर/करीमगंज (एनडब्ल्यू-16 आईबीपी मार्ग से)

इस योजना में राष्ट्रीय जलमार्ग-1, राष्ट्रीय जलमार्ग-2 और राष्ट्रीय जलमार्ग-16 पर माल की आवाजाही को शामिल किया गया है, जिससे आसपास के क्षेत्रों को लाभ होगा और जलमार्ग परिवहन के प्रति भरोसा बढ़ेगा।

2. अंतर्देशीय जहाजों तक टन भार कर का विस्तार

बजट के दौरान 1 फरवरी, 2025 को घोषित टन भार की कर व्यवस्था को भारतीय पोत अधिनियम, 2021 के तहत पंजीकृत अंतर्देशीय जहाजों तक बढ़ा दिया गया है ।

- लाभ: यह लाभ के बजाय पोत के टन भार पर आधारित एक स्थिर और पूर्वानुमानित कर व्यवस्था प्रदान करता है। इससे कर का बोझ कम होता है और अंतर्देशीय शिपिंग को व्यापक रूप से अपनाने को प्रोत्साहन मिलता है।

3. निजी निवेश के लिए नियामक ढांचा

राष्ट्रीय जलमार्ग (जेट्टी/टर्मिनलों का निर्माण) विनियम, 2025 को अधिसूचित किया गया है। यह जेट्टी और टर्मिनलों के निर्माण और प्रबंधन के लिए एक स्पष्ट कानूनी और परिचालन ढांचा स्थापित करके अंतर्देशीय जलमार्ग बुनियादी ढांचे में निजी निवेश को सक्षम बनाता है।

4. बंदरगाह एकीकरण

निर्बाध मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स सुनिश्चित करने के लिए, वाराणसी, साहिबगंज और हल्दिया में मल्टी-मॉडल टर्मिनल, साथ ही कालूघाट में इंटरमॉडल टर्मिनल को संचालन और प्रबंधन के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, कोलकाता में स्थानांतरित किया जा रहा है। इस एकीकरण से

बंदरगाहों और अंतर्देशीय जलमार्गों के बीच माल की आवाजाही को सुव्यवस्थित करने की उम्मीद है।

5. डिजिटलीकरण और केंद्रीकृत डेटाबेस

अंतर्देशीय जहाजों और चालक दल के पंजीकरण के लिए एक केंद्रीकृत पोर्टल विकसित किया जा रहा है। यह सड़क परिवहन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली 'वाहन' और 'सारथी' प्रणालियों के समान है। इस पहल के लाभ:

- पंजीकरण प्रक्रिया को सरल बनाना
- जहाज और चालक दल की उपलब्धता पर वास्तविक समय डेटा प्रदान करना
- क्षेत्र में पारदर्शिता और नियोजन को बढ़ावा देना

6. कार्गो एकत्रीकरण अवसंरचना

जलमार्गों के किनारे विरल औद्योगिक उपस्थिति से सम्बंधित मुद्दों को हल करने के लिए, कार्गो एकत्रीकरण केंद्रों का विकास किया जा रहा है:

- वाराणसी में मालगाड़ी स्थान
- साहिबगंज में एकीकृत क्लस्टर-सह-लॉजिस्टिक्स पार्क

राष्ट्रीय राजमार्ग लॉजिस्टिक्स प्रबंधन लिमिटेड (एनएचएलएमएल) और भारतीय बंदरगाह एवं रेल कंपनी लिमिटेड को इन लॉजिस्टिक्स केंद्रों को विकसित करने और रेल संपर्क प्रदान करने के लिए नियुक्त किया गया है।

7. भारत-बांग्लादेश प्रोटोकॉल मार्ग संचालन

माइया और सुल्तानगंज के बीच मार्ग संख्या 5 और 6 का भारत-बांग्लादेश प्रोटोकॉल के तहत सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। बांग्लादेश सरकार की सहमति के बाद नियमित संचालन शुरू हो जाएगा।

8. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) के साथ सहभागिता

140 से अधिक सार्वजनिक उपक्रमों को उनके कार्गो के एक हिस्से की ढुलाई आईडब्ल्यूटी से करने की संभावना तलाशने के लिए शामिल किया गया है। पेट्रोलियम, उर्वरक, कोयला, इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालयों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने कार्गो आंदोलन की योजनाओं को समुद्री भारत दृष्टिकोण के मॉडल शिफ्ट लक्ष्यों के साथ संरेखित करें।

अंतर्देशीय जल परिवहन के लिए बुनियादी ढांचे का विकास:

- फेयरवे रखरखाव: पोत नौवहन के लिए 35/45 मीटर चौड़ाई और 2.0 से 3.0 मीटर की गहराई बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय जलमार्गों (एनडब्ल्यू) पर चल रहे नदी प्रशिक्षण, ड्रेजिंग, चैनल मार्किंग और सर्वेक्षण।
- राष्ट्रीय जलमार्ग-1 (गंगा नदी): 49 सामुदायिक जेटी, 20 फ्लोटिंग टर्मिनल, तीन मल्टी-मॉडल टर्मिनल (एमएमटी) और 1 इंटर-मॉडल टर्मिनल (आईएमटी) का निर्माण किया गया, साथ ही पांच पूर्व-मौजूदा टर्मिनल भी बनाए गए।
- राष्ट्रीय जलमार्ग-2 (ब्रह्मपुत्र नदी): 12 फ्लोटिंग टर्मिनल, पांडु, जोगीघोपा में एमएमटी, और नदी कार्गो/क्रूज़ जहाजों के लिए बोगीबील और धुबरी में टर्मिनल। जोगीघोपा, पांडु, बिस्वनाथ घाट और नेमाटी में 4 समर्पित घाटों का निर्माण किया गया।
- राष्ट्रीय जलमार्ग-3 (पश्चिमी तट नहर, केरल): गोदामों के साथ 9 स्थायी टर्मिनल और दो रोल-ऑन/रोल-ऑफ (रो-रो) टर्मिनलों का निर्माण किया गया।
- राष्ट्रीय जलमार्ग-68 (गोवा): 2020 में तीन, 2022 में पानी पर तैरती हुई (फ्लोटिंग) एक कंक्रीट जेटी मंडोवी नदी में स्थापित की जाएगी।
- राष्ट्रीय जलमार्ग-4 (कृष्णा नदी, आंध्र प्रदेश): चार पर्यटक जेटी चालू की गईं।
- अन्य परियोजनाएं: उत्तर प्रदेश में मथुरा-वृंदावन खंड में राष्ट्रीय जलमार्ग-110 (यमुना नदी) पर 12 फ्लोटिंग जेटी, बिहार में राष्ट्रीय जलमार्ग-73 (नर्मदा नदी) पर दो जेटी और राष्ट्रीय जलमार्ग-37 (गंडक नदी) पर दो जेटी का निर्माण कार्य चल रहा है।

सतत भविष्य की ओर अग्रसर

भारत द्वारा अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास के लिए किए गए ठोस प्रयासों से महत्वपूर्ण परिणाम सामने आए हैं। इसमें रिकॉर्ड कार्गो मूवमेंट और विस्तारित बुनियादी ढांचा शामिल है। रणनीतिक निवेश, नीतिगत पहल और डिजिटल नवाचारों का संयोजन से देश अंतर्देशीय जल परिवहन क्षेत्र का विस्तार करने में सक्षम बनता है। इससे टिकाऊ परिवहन और आर्थिक विकास में योगदान मिलता है। आने वाले दशकों के लिए निर्धारित महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को प्राप्त करने में इन क्षेत्रों पर निरंतर ध्यान केंद्रित करना महत्वपूर्ण होगा।

संदर्भ

- https://pib.gov.in/PressReleseDetailm.aspx?PRID=2116161&reg=3&lang=1
- https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2121940
- https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/184/AU782_86Mb1w.pdf?source=pqals

- https://iwai.nic.in/chairmans-desk
- https://sansad.in/getFile/loksabhaquestions/annex/184/AU5731_91LDMl.pdf?source=pqals

Click here to see in PDF

पीडीएफ में देखने के लिए यहां क्लिक करें

***

एमजी/केसी/वीके/एसके

(Release ID: 2124061)